

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : नन्दकिशोर राजोरा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 37/2017

अपीलांत

1. वलमकंवर पत्नी मापसिंह, उम्र 35 वर्ष
2. मु.सुखकंवर बेवा रणजीतसिंहजी उम्र 75 वर्ष
3. नैनसिंह पुत्र रणजीतसिंहजी उम्र 54 वर्ष
4. भाखरसिंह पुत्र रणजीतसिंह जी उम्र 38 वर्ष तमाम कौम राजपूत, निवासीगण ऐलाना, तहसील व जिला जालोर

बनाम

रेस्पोंडेन्ट्स



1. अजीतसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंहजी उम्र 41 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी ऐलाना, तहसील व जिला जालोर
2. नारायणसिंह पुत्र रणजीतसिंहजी, उम्र 58 वर्ष
3. हुकमसिंह पुत्र रणजीतसिंहजी, उम्र 49 वर्ष, जातियान राजपूत, निवासीगण ऐलाना तहसील व जिला जालोर
4. घेवरसिंह पुत्र केसाजी, जाति रावणा राजपूत, निवासी ऐलाना, तहसील व जिला जालोर
5. बाबू पुत्र तगा के कायम मुकाम—
 - 5/1 भमरी देवी पत्नी बाबू
 - 5/2 लक्ष्मणसिंह पुत्र बाबू
 - 5/3 भरतसिंह पुत्र बाबू
 - 5/4 दिनेशसिंह पुत्र बाबू, जातियान रावणा राजपूत, निवासीगण ऐलाना, हाल देबावास, तहसील आहोर, जिला जालोर।
6. थाना पुत्र तगा के कायम मुकाम—
 - 6/1 उगमदेवी पत्नी थाना
 - 6/2 बलवंतसिंह पुत्र थाना
 - 6/3 विजयसिंह पुत्र थाना
 - 6/4 जयसिंह पुत्र थाना, जातियान रावणा राजपूत, निवासीगण ऐलाना, हाल देबावास, तहसील आहोर, जिला जालोर।
7. शंकरसिंह पुत्र केसाजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

8. सुखसिंह पुत्र केसाजी
9. इन्द्रसिंह पुत्र केसाजी
10. उत्तमसिंह पुत्र केसाजी, जातियान रावणा राजपूत, निवासी ऐलाणा, तहसील व जिला जालोर।
11. बादलीदेवी पत्नी मूलाराम, जाति सरगरा, निवासी ऐलाना, हाल पिजोपुरा, तहसील व जिला जालोर।
12. सांकलिया पुत्र धर्मा
13. मोका पुत्र धर्मा
14. दलाराम पुत्र भगा
15. हिम्मताराम पुत्र भगा
16. मु. पुरी बेवा भगा तमाम जातियान सरगरा निवासी ऐलाना तहसील व जिला जालोर
17. मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा उम्मेदाबाद जरिये शाखा प्रबंधक
18. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जरिये शाखा प्रबंधक
19. सरकार जरिये तहसील जालोर।



अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :-

1. श्री सुरेन्द्र कुमार दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. रेस्पोजेन्ट अधिवक्ता हुक्मीचंद पारख अनुपस्थित
3. शेष रेस्पोजेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 19 की ओर से

—: निर्णय :-

दिनांक : 30/9/22

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी जालोर द्वारा मुकदमा संख्या 48/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया। रेस्पोजेन्ट संख्या 01 से 18 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उक्त पक्षकार के विरुद्ध गुणवागुण पर निर्णय पारित किया जाता है। वकील अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोजेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा ऐलाणा के खसरा नंबर 1095, 1096, 1110, 1101, 1104, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122 कुल रकबा 23.23 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर उक्त आराजी का बंटवाडा कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोजेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली तलबी हेतु दिनांक 15.06.2017 को नियत की गई। उसके पश्चात दिनांक 20.06.2017 को प्रतिवादीगण को बगैर नोटिस तामिल हुए बगैर जवाब दावा पेश करने का अवसर दिये लोक अदालत कैम्प ऐलाणा में जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय में कार्यालय से अपीलांट एवं रेस्पोजेन्ट संख्या 02 से 19 को किसी प्रकार का नोटिस न तो न्यायालय में उपस्थित होने एवं न ही लोक अदालत कैम्प में उपस्थित होने हेतु जारी किया गया। धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार बंटवाडे के प्रकरणों में पहले प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है एवं उसके एक माह के पश्चात अंतिम डिक्री जारी की जाती है। किन्तु उक्त प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी नहीं की गई। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के निर्देशानुसार लोक अदालत में वो ही दावे व प्रार्थना पत्र निस्तारण किये जा सकते है जिनमे पक्षकारान की आपसी सहमति व रजामंदी हो। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट एवं रेस्पोजेन्ट संख्या 02 से 19 को नोटिस विधिवत तामिल करवाये, बिना सुनवाई का अवसर दिये लोक अदालत कैम्प में विधि विरुद्ध तरीके से जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधि विरुद्ध है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर पत्रावली रिमांड फरमाई जावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेस्पोजेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा ऐलाणा के खसरा नंबर 1095, 1096, 1110, 1101, 1104, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122 कुल रकबा 23.23 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर उक्त आराजी का बंटवाडा कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोजेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वाद दिनांक 15.06.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली तलबी हेतु दिनांक 20.06.2017 को नियत की गई थी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

उसके पश्चात दिनांक 20.06.2017 को पत्रावली न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत ऐलाणा में रखकर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोजेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज कर पत्रावली दिनांक 20.06.2017 को तलबी हेतु नियत की गई थी। किन्तु अपीलाण्ट्स को जारी नोटिस/सम्मन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, और न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत कैम्प ऐलाणा में उपस्थिति हेतु नोटिस पत्रावली पर उपलब्ध है। जिससे स्पष्ट होता है कि दिनांक 20.06.2017 को पत्रावली न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत में रखकर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण को लोक अदालत की सूचना हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया एवं न ही न्यायालय में उपस्थित होने बाबत कोई नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये केवल मात्र एक पेशी के दौरान पत्रावली न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत में रखकर आनन-फानन में जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ने प्राथमिक डिक्री जारी किये बिना प्रकरण में सीधे ही अंतिम डिक्री जारी कर दी, जबकि धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत बंटवाड़े के प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर संबंधित तहसीलदार से बंटवाड़ा प्रस्ताव मंगवाये जाते हैं। उसके पश्चात उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव के आधार पर अंतिम निर्णय व डिक्री जारी की जाती है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में धारा 53 के प्रावधानों का पूर्णतया उल्लंघन करते हुए सीधे ही अंतिम निर्णय व डिक्री की है। जो कि पूर्णतया विधि विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री लोक अदालत कैम्प ऐलाणा में बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये पारित की गई है। अब उक्त प्रकरण में कानूनी बिन्दु यह उद्भूत होता है कि क्या बिना आपसी सहमति के राजस्व लोक अदालत कैम्प में निर्णय पारित किया जाना उचित है ? इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर०सी०आर० (सिविल) 2006(4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Legal Services Authorities Act 1987, Section 20- Power of disposal of cases by Lok Adalat- No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the



parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise" and "settlement". The former expression means settlement of differences by mutual concessions. It is an agreement reached by adjustment of conflicting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms deLey, compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon". The word "compromise" implies some element of accommodation on each side. It is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settlement" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order can be passed by the Lok Adalat " इसी प्रकार एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त न्यायिक सिद्धान्तों से यह स्पष्ट है कि राजस्व लोक अदालत के माध्यम से निर्णय पारित करने हेतु दोनों पक्षों की उपस्थिति एवं उनमें राजीनामा होना आवश्यक है, बिना राजीनामे के लोक अदालत के तहत आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतया प्रभावित होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को बिना नोटिस जारी किये, बिना सुनवाई का अवसर दिये, बिना तनकीयात कायम किये उन पर संग्रहित साक्ष्यों पर तनकीयात विनिश्चय किये प्रशासन गांवो के संग लोक अदालत कैम्प में धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का पूर्णतया उल्लंघन करते हुए विधि विरुद्ध जैर अपील निर्णय व डिक्री की गई है, जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। तथा उपखंड अधिकारी जालोर द्वारा मुकदमा संख्या 48/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य, सुनवाई का




राजस्व अपील प्राधिकरण
पाली

समुचित अवसर प्रदान करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल एवं धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विहित प्रावधानों की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 30-9-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(नन्द किशोर राजोरा)
राजस्थान अपील प्राधिकारी,
पाली